



Neutral Citation No-2026:AHC:9495

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4848 वर्ष 2025

जवाहर लाल ..... याचिकाकर्ता

बनाम

समेकन के उप निदेशक और 10 अन्य ..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: प्रमोद कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षी संख्या-1, 2 और 3 के स्थायी अधिवक्ता को प्रस्तुत रिट याचिका के प्रवेश चरण में सुना।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है, जिसमें समेकन उप निदेशक (संक्षिप्तता में 'डी.डी.सी.')
- द्वारा पुनरीक्षण संख्या-000414 वर्ष 2024(जवाहर लाल बनाम अशर्फी और अन्य) में पारित आदेश दिनांक 28.06.2025 का उल्लंघन किया गया है, जिसमें यूपी चकबंदी/जोत एक्ट की धारा 9A(2) के तहत केस संख्या-278 में चकबंदी अधिकारी (संक्षिप्तता में 'सीओ') द्वारा पारित दिनांक 12.06.2013 के आदेश की पुष्टि की गई है (संक्षिप्तता में, 'यू.पी.सी.एच. अधिनियम'), जिसके तहत प्रतिपक्षी संख्या-4, 5 और प्रतिपक्षी संख्या-6 से 11 के हित में पूर्ववर्ती द्वारा पेश किए गए संशोधन आवेदन को 500/- रुपये (केवल पांच सौ) की लागत के भुगतान के अधीन अनुमति दी गई थी।
3. अभिलेखों से निकाले गए तथ्य यह हैं कि दोनों पक्ष सामान्य पूर्वज सूरज के संपार्श्विक वंशज वंशज हैं, और खाता संख्या-16 पर दर्ज किए गए थे। सभी सह-हिस्सेदार ने यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत अलग-अलग आपत्तियां दायर कीं, जिसमें संबंधित संपत्ति में उनके संबंधित शेयरों की सीमा तक अलग-अलग / विभाजन की मांग की गई। इसके आगे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अशर्फी (प्रतिपक्षी संख्या-4), बैजू (प्रतिपक्षी संख्या-5), द्वारिका (प्रतिपक्षी संख्या-6 से 11 के हित में पूर्ववर्ती) और एक पियरे लाल ने यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत अपने संयुक्त 1/4 हिस्से का दावा करते हुए 20.10.1992 को एक सामान्य आपति दर्ज की। सहायक चकबंदी अधिकारी ने दिनांक 04.11.1992 के अपने आदेश के तहत सभी सह-हिस्सेदार के शेयरों पर निर्णय लेने के लिए मामले को सी.ओ. के समक्ष भेज दिया। सी.ओ. ने दिनांक 20.01.1993 के आदेश के माध्यम से संबंधित संपत्ति में पक्षगण के शेयरों का फैसला किया। इससे व्यथित होकर, जंगल के बैजू, पियरे, अशर्फी और द्वारिका पुत्रों ने दिनांक 06.12.1995 को बहाली आवेदन दायर किया और दिनांक 20.01.1993 के आदेश को वापस लेने की मांग की। सी.ओ. ने बहाली आवेदन की अनुमति दी, 20.01.1993 के अपने आदेश को वापस ले लिया और कार्यवाही को उसके मूल संख्या-पर बहाल कर दिया। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, प्रतिपक्षी प्रतिपक्षियों ने 20.05.2006 को एक संशोधन आवेदन दायर किया, जिसमें संबंधित संपत्ति में 1/3 हिस्से का दावा किया गया। सी.ओ. ने दिनांक 12.06.2013 के आदेश के तहत संशोधन आवेदन की अनुमति दी। संशोधन आवेदन की अनुमति देने वाले आदेश से व्यथित होने के बाद, प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 48 के तहत संशोधन को प्राथमिकता दी। डी.डी.सी. ने दिनांक 28.06.2025 के आदेश के माध्यम से सी.ओ. द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए संशोधन को खारिज कर दिया, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सी.ओ. और डी.डी.सी. द्वारा पारित आदेशों का विरोध करते हुए, दो गुना प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं; सबसे पहले यह कि संशोधन आवेदन अत्यधिक देर से दायर किया गया था, इसलिए, इसे लैच के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था; और दूसरा, संशोधन आवेदन के माध्यम से, चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने पक्षगण के शेयरों के संबंध में अपनी पिछली स्वीकारोक्ति वापस ले ली, क्योंकि उन्होंने शुरू में 1/4 शेयर स्वीकार किया था, लेकिन बाद में 1/3 शेयर का दावा किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया है कि, 20.01.1993 के आदेश के बाद, प्रतिपक्षी प्रतिपक्षियों ने यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत एक और आपति दर्ज की, जिसे 27.01.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था; इस प्रकार, कार्रवाई के समान कारण के लिए पहले की कार्यवाही में संशोधन आवेदन कानून की नजर में टिकाऊ/पुख्ता नहीं था।

5. मैं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पेश की गई पहली प्रस्तुति से सहमत नहीं हूँ कि संशोधन आवेदन निर्धारित अवधि की सीमा के बाद दायर किया गया था। प्रारंभिक चरण में या अपील या पुनरीक्षण के चरण में दलीलों में संशोधन आवेदन को आगे बढ़ाने के प्रयोजनों के लिए यू.पी.सी.एच. अधिनियम के तहत कोई विशिष्ट प्रावधान प्रदान नहीं किया गया है। दीवानी प्रक्रिया संहिता (सी.पी.सी.) के सामान्य सिद्धांत, अधिक से अधिक, संशोधन मामलों पर लागू किए जा सकते हैं, हालांकि सी.पी.सी. के प्रावधान यू.पी.सी.एच. अधिनियम के तहत प्रतिपादित कार्यवाही पर सख्ती से लागू नहीं होते हैं। विजय नारायण सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य, एआईआर 1970 ऑल 241(एफबी) में इस न्यायालय के माननीय पूर्ण पीठ के फैसले ने माना कि यह नहीं माना जा सकता है कि सी.पी.सी. के सभी प्रावधानों में सी.पी.सी. के आदेश VI नियम 17 में प्रावधान है कि अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षकारों को अपनी दलीलों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकती है, बशर्ते कि परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ध्यान रखना उचित है, जैसा कि अभिलेखों से उभरा है, कि सभी सह-शेयररों द्वारा दायर आपत्तियां, जिसमें प्रतिपक्षियों द्वारा दायर 20.10.1992 की आपत्ति भी शामिल है, को सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 4.11.1992 के आदेश के तहत सी.ओ. को भेजा गया था। बदले में, सी.ओ. ने 20.01.1993 को एक लापरवाह तरीके से आदेश पारित किया, केवल खाता संख्या-16 में कुछ सह-हिस्सेदार के शेयरों का संकेत दिया। इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि आदेश में उल्लिखित शेयरों के लिए पार्टियां कैसे हकदार हैं। इसके अलावा, पक्षों के शेयरों का निर्णय लेते हुए सी.ओ. द्वारा पारित दिनांक 20.01.1993 के उपरोक्त आदेश को बाद में वापस ले लिया गया और यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत मूल कार्यवाही बहाल कर दी गई। हालांकि, इस बीच, यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिपक्षी प्रतिपक्षियों सहित शेष सह-शेयरर द्वारा दायर एक नई आपत्ति को 27.1.2006 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत पहले की आपत्ति का फैसला पहले ही 20.01.1993 के आदेश द्वारा किया जा चुका था।

6. यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेखों पर कुछ भी नहीं है कि प्रस्तुत याचिकाकर्ता या उनके पूर्ववर्ती ने प्रतिपक्षियों के इशारे पर यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत कार्यवाही



में कोई विस्तृत आपत्ति दर्ज की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाही की बहाली के बाद पक्षों के साक्ष्य के लिए सामान्य तिथियां तय की जा रही थीं। हालांकि, इस अवधि के दौरान, प्रतिपक्षी प्रतिपक्षियों ने दो सह-हिस्सेदारों, अर्थात् जगई और पियारे लाल की मृत्यु के कारण संबंधित संपत्ति में अपने शेयरों को स्पष्ट करने के लिए संशोधन आवेदन दायर किया। 27.01.2006 के आदेश के तुरंत बाद 20.05.2006 को संशोधन आवेदन पेश किया गया था, जिसके तहत यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत बाद की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था। इसलिए, प्रस्तुत मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिपक्षी प्रतिपक्षियों की ओर से पेश किए गए संशोधन आवेदन को इस लैच के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

7. मुझे याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पेश की गई दूसरी प्रस्तुति पर भी संदेह है जो कि प्रतिपक्षियों द्वारा किए गए प्रवेश की कथित वापसी से संबंधित है। अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत दिनांक 20.10.1992 की आपत्ति में, चुनाव लड़ने वाले प्रतिपक्षियों ने एक पियारे लाल के साथ खाता संख्या-16 में संयुक्त 1/4 हिस्से का दावा किया था; इसके अलावा, उन्होंने अपने व्यक्तिगत शेयरों को 1/24 वें प्रत्येक होने के लिए समझाया। संशोधन आवेदन में उल्लिखित पक्षकारों के वंशावली वृक्ष का उल्लेख करना उचित होगा, जो दर्शाता है कि सूरज (सामान्य पूर्वज) के तीन बेटे बादल, पंचू और भागी थे। याचिकाकर्ता पंचू का वंशज है, जबकि प्रतिपक्षी भागी के वंशज हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता धन्नी का बेटा है, जो पंचू का बेटा था, जबकि प्रतिपक्षी जंगली के बेटे हैं, जो भागी का बेटा था। बादल के उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को प्रस्तुत रिट याचिका के कारण शीर्षक में शामिल नहीं किया गया है। संशोधन आवेदन बाद की घटना के कारण दायर किया गया था, जाहिर है, जगई (जंगल के भाई) और पियारे, (जंगल के चौथे बेटे) की मृत्यु के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त दो मौतों, भागी की शाखा में वंशजों के कारण, संशोधन आवेदन को प्रतिपक्षी प्रतिपक्षियों द्वारा खाता संख्या-16 में अपने संबंधित शेयरों शेयरों को फिर से जांचने और समझाने के लिए पेश किया गया था। यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत मूल आपत्ति में, जंगल के सभी चार पुत्रों, बैजू, पियारे, अशर्फी और द्वारिका ने भागी के 1/4 हिस्से की सीमा तक अपने संयुक्त हिस्से के लिए राहत मांगी थी। बाद में उन्होंने जगई और पियारे की मौत के कारण संशोधन की मांग की। प्रस्तुत याचिकाकर्ता



यह प्रदर्शित करने में विफल रहा कि उसे प्रतिपक्षी प्रतिपक्षियों द्वारा दिए गए प्रवेश से कैसे विस्थापित किया गया है। इस मोड़ पर, पक्षगण के शेयरों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। संशोधन आवेदन में दी गई वंशावली और विचाराधीन संपत्ति में सह-हिस्सेदार के शेयर सी.ओ. के समक्ष अंतिम निर्णय का विषय है। संशोधन आवेदन, बाद की घटना के कारण, पियारे और जगई की मृत्यु के कारण दायर किया गया था, को प्रतिपक्षी द्वारा पहले की गई किसी भी स्वीकार्यता को वापस लेने के रूप में नहीं माना जा सकता है। बल्कि, चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने बदले हुए तथ्यात्मक परिदृश्य में अपने शेयरों को समझाने या पुनः व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। कहने की जरूरत नहीं है कि मूल कार्यवाही में जंगल के बेटों ने अपने व्यक्तिगत शेयरों का दावा किया था, प्रत्येक वर्ष 1/24 वीं सीमा तक; जबकि संशोधन आवेदन में उन्होंने अपने व्यक्तिगत शेयरों का दावा वर्ष 1/9 वें शेयर की सीमा तक किया और तदनुसार, प्रश्न में संपत्ति में 1/3 शेयर की सीमा तक अपने संयुक्त हिस्से में सुधार की मांग की। सी.ओ. के साथ-साथ डी.डी.सी. ने देखा है कि सी.ओ. के समक्ष सभी आवेदक अनपढ़ व्यक्ति हैं जो केवल आवेदन पर अपने अंगूठे का निशान लगाते हैं।

9. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुझे प्रस्तुत रिट याचिका पर विचार करने या सी.ओ. और डी.डी.सी. द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई उचित आधार नहीं मिलता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में इस न्यायालय की कृपा को वारंट करने के लिए आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता, अनियमितता, विकृति, दुर्बलता या अस्पष्टता नहीं है। अभिलेखों पर यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रस्तुत याचिकाकर्ता को कैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित किया गया है, या यदि उसके लिए न्याय के हानि/क्षति का कोई कारण बनने की कोई संभावना है, तो आक्षेपित आदेशों का पालन करता है।

10. परिणामस्वरूप, प्रस्तुत रिट याचिका, गलत और योग्यता से रहित होने के कारण, लागत के रूप में बिना किसी आदेश के **खारिज** की जाती है।

11. मामले से अलग होने से पहले, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत मूल कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अंतरिम संरक्षण का आग्रह किया है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के



तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अंतरिम संरक्षण के लिए सी.ओ. के समक्ष एक उपयुक्त आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

12. सी.ओ. से डी.डी.सी. द्वारा दिनांक 28.06.2025 के आदेश के तहत जारी निर्देश के अनुसार आपत्ति पर जल्द से जल्द फैसला करने की उम्मीद है।

जनवरी 14, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)